



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2012/माघ 21, 1933

No. 42]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2012/MAGHA 21, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2012

विषय : तुर्की तथा रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोडा ऐश" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू करने के संबंध में ।

सं. 14/3/2011-डीजीएडो.—यतः, मै. अल्कली मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें तुर्की तथा रूस (जिन्हें एतदपश्चात "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित सोडा ऐश (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है । गुजरात हैवी कैमिकल्स लि. (जी एच सी एल) सौराष्ट्र कैमिकल्स लि. (एस सी एल), निरमा लि. और डी सी डब्ल्यू लि. जो भारत में सोडा ऐश के उत्पादक हैं और एसोसिएशन के सदस्य हैं, ने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन संबंधी संगत सूचना/आंकड़े उपलब्ध कराए हैं ।

2. और, यतः प्राधिकारी ने पाया है कि पाटनरोधी जांच की शुरुआत को उचित ठहराने वाले संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन; घरेलू उद्योग को क्षति, और कथित पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के मौजूद होने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं और इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग की परिणामी क्षति की जांच करने के लिए पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का पता लगाया जा सके और ऐसे पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाएगा तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा ।

घरेलू उद्योग तथा स्थिति

3. यह आवेदन मै. अल्कली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ए एम ए आई) द्वारा गुजरात हैवी कैमिकल्स लि. (जी एच सी एल) सौराष्ट्र कैमिकल्स लि. (एस सी एल), निरमा लि. और डी सी डब्ल्यू लि. की ओर से दायर किया गया है

रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार याचिकाकर्ता कंपनियों का उत्पादन, पी ओ वाई में लगभग 69% रहा है जो कुल भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। अतः आवेदक योग्यता को पूरा करता है और याचिकाकर्ता नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।

आवेदक ने दावा किया है कि जहां तक वर्तमान संबद्ध देशों का संबंध है, याचिकाकर्ता कंपनियों ने न तो संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में उत्पाद के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित रहे हैं। जी एच सी एल की रोमानिया में एक संबंधित कंपनी है और निरमा की अमरीका और फ्रांस में एक संबंधित कंपनी है। तथापि, चूंकि यह याचिका तुर्की और रूस से पाटित आयातों के विरुद्ध है इसलिए प्राधिकारी मानते हैं कि यह संबंध संगत नहीं है।

विचाराधीन उत्पाद

4. विचाराधीन उत्पाद डाई सोडियम कार्बोनेट है जिसे व्यापक रूप से सोडा ऐश के रूप में जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र Na_2CO_3 है। सोडा ऐश एक सफेद, क्रिस्टलीय, जल में घुलनशील सामग्री है। सोडा ऐश दो रूपों में उत्पादित होता है— लाइट सोडा ऐश और डेंस सोडा ऐश। इन दोनों किस्मों में अंतर बल्क घनत्व का है। इसके अलावा, सोडा ऐश या तो प्राकृतिक सोडा ऐश या कृत्रिम सोडा ऐश हो सकता है। दोनों उत्पाद बिल्कुल समान हैं। तथापि, वर्तमान याचिका में सोडा ऐश की सभी किस्में और रूप शामिल हैं।

सोडा ऐश को कृत्रिम तरीके और प्राकृतिक तरीके के माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है। प्राकृतिक सोडा ऐश के मामले में विलायन की प्रक्रिया अपनाई जाती है जहां सोडियम कार्बोनेट के प्राकृतिक भंडार भारी मात्रा में मौजूद हो। सिंथेटिक सोडा ऐश के मामले में विभिन्न प्रकार की कृत्रिम प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। जहां प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध न हों, जैसा कि भारत के मामले में है।

भारत में सोल्वे प्रक्रिया या डूअल प्रक्रिया और अक्जो ब्राइ लाइम प्रक्रिया के रूप में सामान्यतः ज्ञात संशोधनों का प्रयोग सोडा ऐश के विनिर्माण में किया जाता है। सोडा ऐश के उत्पादन के लिए अपेक्षित प्रमुख कच्ची सामग्री नमक और चूना पत्थर है। सोल्वे प्रक्रिया में अपरिष्कृत जल में कच्चे सोल्डर साल्ट को घोलकर तैयार किए गए अपरिष्कृत ब्राइन को

शुद्धिकृत ब्रायन तैयार करने के लिए चूने और सोडा ऐश के मिल्क के प्रयोग द्वारा शुद्धिकृत किया जाता है। तत्पश्चात् इसे अमोनिएटेड ब्रायन तैयार करने के लिए अमोनिया अवशोषक में एमोनिएट किया जाता है। एमोनिएटेड ब्रायन को प्रेसीपिटेड सोडियम बाई कार्बोनेट के लिए कार्बोनेट किया जाता है। तत्पश्चात् इसे पृथक् अपरिष्कृत बाय कार्बोनेट केक के लिए छाना जाता है जिसे आगे लाइट सोडा ऐश में रूपांतरित करने के लिए गर्म किया जाता है। अक्जो ड्राइलाइम प्रक्रिया इस हद तक परंपरागत सोल्वे प्रक्रिया में बदलाव है कि लाइमस्लरी का मिल्क तैयार नहीं किया जाता है और लाइम के हाइड्रेशन का ताप और रासायनिक प्रतिक्रिया मूल तरल को उबलने के तापमान तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त होती है। इस प्रकार सोल्वे प्रक्रिया की तुलना में डिस्टिलेशन प्रक्रिया में भाप और चूने की खपत कम होती है। डुअल प्रक्रिया में अमोनिया रिकवरी इकाई और मिल्क ऑफ लाइम सेक्शन को निस्सारित किया जाता है और अमोनिया क्लोराइड सेक्शन अमोनिया क्लोराइड के क्रिस्टलाइज और प्राप्त होने के स्थान पर विद्यमान होता है।

सोडा ऐश डिटरजेंट, साबुन, सफाई के सामान, सोडियम आधारित रासायनों, फ्लोट ग्लास, कंटेनर और विशेष ग्लासों, सिलिकेटों और अन्य औद्योगिक रसायनों के विनिर्माण में एक प्रमुख अवयव है। वस्त्रों, कागज, धात्विक उद्योगों और डीसेलिनेशन संयंत्रों में भी इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है।

सोडा ऐश एक अकार्बनिक रसायन है। इसे सी शु. टेरिफ अधिनियम के अध्याय 28 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, यह सी.शु. उपशीर्ष स 2836.20 के अंतर्गत आता है। तथापि, सी.शु. वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

आवेदक ने दावा किया है कि भारत में पाटन की जा रही संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। पाटित आयातों तथा घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच न तो तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता कार्यों और न ही अंतिम प्रयोगों की दृष्टि से कोई अंतर है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत इन्हें "समान वस्तु" माना जाना चाहिए।

प्राधिकारी वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" मानते हैं।

संबद्ध देश

वर्तमान जांच में शामिल देश तुर्की और रूस हैं।

सामान्य मूल्य

7. आवेदक ने अनुरोध किया है कि वे इन देशों में किए गए वास्तविक सौदों का कोई साक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहे हैं। तथापि, आवेदक को हरीमन कैमसल्ट द्वारा प्रकाशित

क्लोर अल्कली, जो सोडा ऐश सहित विभिन्न अल्कली उत्पादों की कीमतों को नियमित रूप से प्रकाशित करता है, के अनुसार रूस के घरेलू बाजार में प्रचलित कीमतों के साक्ष्य मिले हैं। क्लोर अल्कली तुर्की में सोडा ऐश की कीमतें प्रकाशित नहीं करता है। तथापि, क्लोर अल्कली यूरोप में सोडा ऐश की कीमतें प्रकाशित करता है। आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि यूरोप में सोडा ऐश की कीमत तुर्की के घरेलू बाजार में प्रचलित कीमतों की अच्छी संकेतक हैं। इसके अलावा, चूंकि यह पत्रिका उच्च और निम्न कीमतों को दर्शाती है इसलिए आवेदक ने भारत औसत कीमत अपनाई है। आवेदक द्वारा किए गए सामान्य मूल्य के दावों पर जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है।

निर्यात कीमत

8 आवेदक ने दिसंबर, 2011 तक डी जी सी आई एंड से प्राप्त आंकड़ों और उसके बाद की अवधि के लिए आई बी आई एस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है। निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय भाड़ा और पत्तन व्ययों के लिए कीमत समायोजन की अनुमति दी गई है।

पाटन मार्जिन

9. आवेदक ने इस बात के पर्याप्त साक्ष्य दिए हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का भारत में पाटन हो रहा है और इससे पाटनरोधी शुल्क जांच की शुरुआत भी न्यायोचित है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

10. आवेदक ने पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती, घरेलू उद्योग की कम कीमत पर बिक्री और लाभप्रदता में गिरावट नियोजित पूंजी पर आय और नकद प्रवाह में गिरावट के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण आवेदक द्वारा उठाई जा रही क्षति के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जो पाटनरोधी जांच को न्यायोचित ठहराते हैं।

जांच अवधि

वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पी ओ आई) 1 जुलाई, 2010 से 30 सितंबर, 2011 (15 महीने) है। तथापि, क्षति अवधि में अप्रैल, 08 से मार्च, 09, अप्रैल, 09 से मार्च, 10, अप्रैल, 10 से मार्च, 11 और जांच अवधि शामिल है। वास्तविक क्षति के खतरे के लिए जांच अवधि के बाद के आंकड़ों की भी जांच की जा सकती है।

सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों और भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, संबद्ध वस्तु के साथ संबंधित समझे जाने वाले भारत के आयातक और प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को विहित ढंग और तरीके से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग-अलग पत्र लिखे जा रहे हैं ताकि वे संगत सूचना प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकें। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकता है। सूचना/अनुरोध निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं :

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार,
उद्योग भवन,
कमरा नं. 240,
नई दिल्ली-110 011

समय सीमा

13. इस जांच से संबंधित कोई सूचना जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की तारीख से 40 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित उल्लिखित पते पर लिखित रूप में प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

14. सभी हितबद्ध पक्षकार पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 (1) के अनुसार प्रदत्त गोपनीय सूचना, यदि कोई हो, के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करेंगे। गोपनीय सूचना के ऊपर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अवश्य लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर सूचना को अगोपनीय माना जाएगा। गोपनीय सूचना का अगोपनीय अंश या अगोपनीय सारांश पर्याप्त ब्यौरे में होना चाहिए जिससे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचना की सार्थक समझ मिल सके। यदि सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है तो तत्संबंधी कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

उपर्युक्त पैरा में किसी बात के होते हुए भी यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या वह सामान्य अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन के लिए प्राधिकृत नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

15. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कोई भी हितबद्ध पक्षकार कर सकता है ।

असहयोग

16. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना देने से मना करता है और अन्यथा तर्कसंगत अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रस्तुत नहीं करता है या जांच में काफी बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties)

Initiation Notification

New Delhi, the 10th February, 2012

Subject : Initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of 'Soda Ash' originating in or exported from Turkey and Russia.

No. 14/3/2011-DGAD.—M/s Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of 'Soda Ash' (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from Turkey and Russia (hereinafter also referred to as the subject countries). Gujarat Heavy Chemicals Limited (GHCL), Saurashtra Chemicals Limited (SCL), Nirma Limited and DCW Limited, who are the producers of Soda Ash in India and are the members of the Association, have provided relevant information/data for alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

2. And whereas, the Authority finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries; 'injury' to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exists to justify initiation of an anti-dumping investigation, the Authority, hereby, initiates anti-dumping duty investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Domestic Industry & Standing

3. The Application has been filed by M/s Aikali Manufacturers' Association of India (AMAI) on behalf of Gujarat Heavy Chemicals Limited (GHCL), Saurashtra Chemicals Limited (SCL), Nirma Limited, and DCW Limited.

As per information available on record, production of the petitioner companies, being almost 69% in the POI, account for a major proportion of total Indian production. The petition, therefore, satisfies standing and petitioner constitutes domestic industry within the meaning of the Rules.

The applicant has claimed that as far as current subject countries are concerned, petitioner companies have neither imported the subject goods nor are they related to any exporter or importer of the subject goods in the subject countries. GHCL has a related company in Romania and Nirma has related company in USA & France. However, since the petition is against dumped imports from Turkey and Russia, the Authority considers that this relationship is not relevant.

Product under consideration

4. The product under consideration is Disodium Carbonate, popularly known as Soda Ash, having chemical formula Na_2CO_3 . Soda Ash is a white, crystalline, water soluble material. Soda Ash is produced in two forms - Light Soda Ash and Dense Soda Ash. The difference in the two types is bulk density. Further, soda ash can be either natural soda ash or synthetic soda ash. Both products are essentially the same. However, the present petition includes all types and form of Soda Ash.

Soda Ash can be produced through synthetic route and natural route. In case of natural soda ash, dissolution process is employed where natural deposits of Sodium Carbonate occur in a large scale. In case of synthetic soda ash, various types of synthetic processes are employed where the natural resources are not available. as is the case in India.

In India, Solvay process or modifications commonly known as Dual Process and Akzo Dry Lime Process is used to manufacture soda ash. Salt and limestone are the major raw materials required for producing soda ash. In Solvay process, the raw brine prepared by dissolving crude soldar salt in raw water is purified by use of milk of lime and soda ash to prepare purified brine which is then ammoniated in ammonia absorber to prepare ammoniated brine. Ammoniated brine is carbonated to precipitate sodium bi-carbonate, which is then filtered to separate crude bi-carbonate cake, which is further heated to decompose into light soda ash. Akzo dry lime process is a modification of the conventional Solvay process to the extent that milk of lime slurry is not prepared and the heat of hydration of lime and of chemical reaction are sufficient to raise the mother liquor to the boiling temperature, thereby, reducing the

450 3/12-3

steam and lime consumption in distillation process as compared to Solvay process. In the dual process, the ammonia recovery unit and milk of lime section are dispensed with and an ammonium chloride section exists where the ammonium chloride is crystallized and recovered.

Soda Ash is an essential ingredient in the manufacture of detergents, soaps, cleaning compounds, sodium based chemicals, float glass, container and specialty glasses, silicates and other industrial chemicals. It is also widely used in textiles, paper, metallurgical industries and desalination plants.

Soda Ash is an inorganic chemical. It is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975, falling under the customs sub-heading no. 2836.20. Customs classification is, however, illustrative only and not binding on the present investigation.

Like Articles

5. The applicant has claimed that the subject goods which are being dumped into India are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. The two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the AD Rules.

The Authority, for the purpose of the present investigation, treats the subject goods produced by the applicant in India as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

Subject Countries

6. The countries involved in the present investigation are Turkey and Russia.

Normal value

7. The Applicant has submitted that they were not able to get any evidence of actual transactions conducted in these countries. However, the applicant has been able to get evidence of prices prevailing in the domestic market of Russia as per the Chlor Alkali published by Harimann Chemsult which regularly publishes prices of various alkali products including Soda Ash. Chlor Alkali does not publish prices of Soda Ash in Turkey. Chlor Alkali, however, publishes prices of Soda Ash in Europe. The applicant has also submitted that price of Soda Ash in Europe is a good indicator of prices prevailing in the domestic market of Turkey. Further, since the Journal mentions high and low prices, applicant has adopted weighted average price. The Normal value claims by the applicant has been considered for the purposes of initiation.

Export Price

8. The applicant has claimed export prices on the basis of data obtained from DGCI&S up to December 2011 and from IBIS for the subsequent period. Price adjustments have been allowed on account of Ocean Freight, Marine Insurance, Inland Freight and Port expenses to arrive at the net export price.

Dumping Margin

9. The applicant has provided sufficient evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices, prima-facie, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject countries are being dumped into India, and justifying initiation of antidumping duty investigation.

Injury and Causal Link

10. The applicant has furnished evidence regarding the 'injury' having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports, price undercutting, price suppression, decline in profitability, return on capital employed and cash flow for the domestic industries. There is sufficient evidence of 'injury' being suffered by the applicant caused by dumped imports from the subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

Period of Investigation

11. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st July 2010 to 30th September 2011 (15 months). The injury investigation period will, however, cover the periods April 2008-March 2009, April 2009-March 2010, April 2010-March 11 and the POI. For threat of material injury, the data beyond the POI would also be examined.

Submission of information

12. The known exporters in the subject countries and their Governments through their Embassies in India, importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below. The information/submissions may be submitted to:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
Room No.240, Udyog Bhawan,
New Delhi -110107.

Time limit

13. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of the notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the AD Rules.

Submission of Information on Non-Confidential basis

14. All interested parties shall provide non-confidential summary in terms of Rule 7 (2) of the AD Rules for the confidential information, if any, provided as per Rule 7 (1) of the AD Rules. Confidential information must be clearly marked as "Confidential", failing which the information will be treated as non-confidential. The non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing information, such information is not susceptible to summary, a statement of reason, thereof, is required to be provided.

Notwithstanding anything contained in the para above, if the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.

Inspection of Public File

15. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the information submitted by other interested parties.

Non-cooperation

16. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority